

निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज)  
पीठासीन अधिकारी-रजनी मीणा ,आर.ए.एस0

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	GCMS NO.	निर्णय दिनांक
24/2024	251 ए	11.12.2024	2024/858	19-01.2025

अनवान

1. श्री प्रमोद मोदी पिता सुरेन्द्र कुमार मोदी जैन उम्र वयस्क निवासी मोदी कॉलोनी, तहसील निम्बाहेडा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, राज. टिनेन्सी एक्ट  
वकील वादी:- श्री योगेन्द्र सिंह सोलंकी

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में की धारा 251-ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि:-

1. प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की आराजी मोजा नन्नाणा प0ह0 नन्नाण तह0 भदेसर में खाता सं0 158 की आ0नं0 793 रकबा 0.43 हैक्टेयर पर प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार आने जाने के रास्ते के संबंध में अनुतोष चाहा है। प्रार्थी उक्त आराजीयात के रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाना चाहता है, ताकि पत्रावली पर सही स्थिति रिकार्ड पर आ सके।
2. यह कि प्रार्थी अपनी आराजी नं0 793 में पहुंचने के लिये सरकारी आ0नं0 791 बीड भूमि के मध्य होकर कदीमी समय से आ जा रहा है परन्तु उक्त आराजी में आने जाने का रास्ता रेकार्डेड तौर से राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज नहीं है, इसलिये वादी ने अपने स्तर पर राजस्व कर्मचारियों से भी रास्ते के संबंध में कार्यवाही करना चाही, परंतु उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत करने को कहा, इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है।



**अतः श्रीमान से निवेदन है कि**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी नम्बर 793 में पहुँचने के लिए सरकारी रास्ते से पश्चिम में मुडकर आराजी नम्बर 790 गे.मु0 रास्ता भूमि से होकर सरकारी बीड भूमि आ0न0 791 के मध्य से दक्षिण से उत्तर दिशा में बढ़ते हुए प्रार्थी की आराजी नम्बर 793 में पहुँचता है, जो मौके पर करीब 20 फीट चौड़ाई में कायम है, उसे राजस्व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कर दर्ज कराया जावे इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी दर अनुसार भुगतान करने के लिए तैयार है

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार भदेसर से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार भदेसर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/798 दिनांक 04.12.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 793 तक पहुँचने के लिए सरकारी रास्ते से पश्चिम में मुडकर आराजी नम्बर 790 गे.मु0 रास्ता भूमि से होकर सरकारी बीड भूमि आ0न0 791 के मध्य से दक्षिण से उत्तर दिशा में बढ़ते हुए प्रार्थी की आराजी नम्बर 793 में पहुँचता है, जो मौके पर करीब 20 फीट चौड़ाई में कायम है, उसे राजस्व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कर दर्ज कराया जाकर नवीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका-रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है-

**धारा 251-क- अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1)**  
जहाँ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे, और उपखण्ड अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

- (1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और  
(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकटतम रूट से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

- (1) जहाँ—उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

- (2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

01. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

**68. Application under Sec. 251-A.** - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.

**69. Enquiry and disposal of application.** - On receipt of an application in Form 1, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the

parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

**70. Determination of compensation.** - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

02. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के तहत सरकारी सिवायचक भूमि से नवीन रास्ता चाहा गया है। सरकारी सिवायचक भूमि से नवीन रास्ता हेतु राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के द्वारा निर्देश जारी

किये हुए हैं। अतः राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 का प्रासंगिक विवरण इस प्रकार है:-

### परिपत्र

**विषय:-राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध में।**

सम्बन्धित खातेदारों की आपसी सहमति से उनके खेतों तक पहुँच के लिए रास्ता गुजरता है या नया रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाता है। यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई राजकीय भूमि पडती है तो उसका भी समाधान किया जा चुका है एवं यदि खातेदार आपस में सहमत नहीं है तो वह खातेदार जिसको जोत तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना है या पुराने रास्ते को चौड़ा करना है तो उनका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-251-क में दिया गया है। लेकिन उक्त प्रावधान केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ते के सम्बन्ध में ही है। लेकिन ऐसे प्रकरण जिसमें खातेदार को अपनी जोत तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। खातेदार राजकीय भूमि में से होकर ही अपनी जोत तक पहुँच सकता है। खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आन-जाने के लिए रास्ता चाहा जा रहा है।

उक्त समस्या के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुँचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जाँच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुँचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम-2004 के नियम-2 के उपनियम-(1) के खण्ड-(ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों पर दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फिट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावेगी तथा उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

03. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि

धारा 251-क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत आमद-रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क निम्न पूर्वशर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार है-

1. खातेदार की रास्ते बाबत अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

04. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार भदेसर की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 22.01.2025 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

05. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार भदेसर की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 04.12.2025 द्वारा लघुत्तम मार्ग बाबत विकल्प को प्रस्तावित किया गया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार भदेसर की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 04.12.2025 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार भदेसर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/789 दिनांक 04.12.2025 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क काबिल-ए-मंजूर है। अतः तहसीलदार भदेसर की दिनांक 04.12.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग की लम्बाई 100 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर गैर मुमकिन रास्ता प्रस्तावित किया है उक्त भूमि को क्षतिपूर्ति भुगतान पश्चात् राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भदेसर को आदेश दिये जाते हैं कि दिनांक 04.12.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट में अंकित प्रस्ताव में इंगित लाल रंग से प्रदर्शित आराजी नम्बर 791 किस्म बिलानाम में से प्रस्तावित रास्ता लम्बाई 100 मीटर एवं चौड़ाई 6

मीटर भूमि को क्षतिपूर्ति भुगतान पश्चात् राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे साथ ही नियमानुसार रास्ते को खाता संख्या-1 सिवायचक में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। दिनांक 04.12.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार भदेसर को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर न्यायालय मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(रजनी मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
भदेसर